पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़

बनाम

मेघ राज गर्ग और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1591/2006)

20 मई 2010

[जी.एस. सिंघवी और सी.के. प्रसाद, जे.जे.]

सेवा कानून:

पंजाब सिविल सेवा नियम:

वॉल्यूम. I, अध्याय II, अनुलग्नक-ए, पैरा I (जैसा कि यह 1994 के संशोधन से पहले था) - जन्म तिथि में सुधार-आयोजित: वैधानिक प्रावधान के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। सरकारी कर्मचारी के सेवा में प्रवेश की तारीख से दो वर्ष के बाद, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार के पास उसके प्रवेश के बारह वर्ष से अधिक समय के बाद संबंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने की शक्ति, क्षेत्राधिकार या अधिकार नहीं था। सेवा - इसलिए, उनमें से किसी ने भी मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन के आधार पर न्यायिक अधिकारी द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार करके कोई अवैधता नहीं की।

प्रतिवादी संख्या 1 की जन्मतिथि., जो मार्च 1973 में उप-न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा में शामिल हुए, मैट्रिक प्रमाणपत्र के अनुसार, सेवा

पुस्तिका में 27.3.1936 दर्ज किया गया था। सेवा में शामिल होने के दस साल बाद, उन्होंने मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में अपनी जन्मतिथि 27.3.1938 को सही करने के लिए आवेदन किया। यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने प्रार्थना की इजाजत दे दी. तदनुसार, प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन किये गये। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने सेवा रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में बदलाव के लिए राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व किया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रार्थना को खारिज कर दिया। प्रतिवादी नंबर 1 ने तब यह घोषित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि राज्य सरकार और उच्च न्यायालय का निर्णय अवैध, शून्य और अप्रभावी था, और एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए प्रतिवादी को 27.3.1936 से सर्विस बुक में उसकी जन्मतिथि बदलने का निर्देश दिया गया था। 27.3.1938 तक. मुक़दमे का फैसला सुनाया गया। निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने डिक्री की पुष्टि की। व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

कोर्ट ने, अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. इस न्यायालय ने बार-बार सिविल अदालतों और उच्च न्यायालयों को सेवा में प्रवेश करने के लंबे समय बाद दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावों पर विचार करने और स्वीकार करने के प्रति आगाह किया है। [पैरा 12] [182-एच; 183-ए]

भारत संघ बनाम हरनाम सिंह (1993) 2 एससीसी 162; सचिव एवं आयुक्त, गृह विभाग एवं अन्य बनाम आर. किरुबाकरन 1994 सप्लिमेंट(1) एससीसी 155 और भारत संघ बनाम सी. राम स्वामी (1997) 3 एससीआर 760, पर निर्भर।

1.2. पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1 के अध्याय II के अनुलग्नक-ए के पैरा 1 को ध्यान में रखते हुए (जैसा कि यह प्रतिवादी नंबर 1 के सेवा में शामिल होने के

समय और उसके सुधार के लिए आवेदन करने की तिथि पर भी था) उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म), जिसका मुकदमे की रखरखाव से संबंधित मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है, की तारीख से दो साल के बाद अपनी दर्ज की गई उम्र में सुधार के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। सरकारी सेवा में उनका प्रवेश. मौजूदा मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 ने सेवा में प्रवेश करने के दस साल बाद मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि को नियम में निर्दिष्ट दो वर्ष की समय सीमा से कहीं अधिक बदलने के लिए आवेदन किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय या उस कारण से राज्य सरकार के पास प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने की शक्ति, क्षेत्राधिकार या अधिकार नहीं था। उनमें से किसी ने भी प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार करके या उसके साथी आईक्यूलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन के आधार पर कोई अवैधता नहीं की। [पैरा 9-11] [179-जी-एच; 180-डी-एच; 181-जी]

1.3. प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने उसे सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन दाखिल करने या अभ्यावेदन करने का कोई कारण नहीं बताया। इसलिए, यह माना जाता है कि सेवा में शामिल होने के बारह साल बाद अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर किया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से गलत था और ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पारित करके एक गंभीर त्रुटि की थी। प्रतिवादी नंबर 1 और निचली अपीलीय अदालत के पक्ष में और उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को रद्द करने से इन्कार करके वही गलती दोहराई। [पैरा 11 और 15] [181-एच; 182-ए; 187-ई-एफ]

केस कानून संदर्भ:

(1993) 2 SCC 162	पर निर्भर	पैरा 12
(1994) Supp.1 SCC 15	निर्भर	पैरा 13
(1997) 3 SCR 760	निर्भर	पैरा 14

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 2006 का 1591.

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के न्यायालय उच्च न्यायालय के आरएसए सं. 901,1996 मे पारित निर्णय और आदेश से 06.09.2002 दिनांकित से.

अपीलकर्ता की ओर से राजीव शर्मा, अभिषेक बर्थरे।

उत्तरदाताओं के लिए-अजीत कुमार, शिखा रॉय (एस.के. सभरवाल के लिए), अजय पाल (एनपी)।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया

जी.एस. सिंघवी, जे. 1. क्या पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 मेघ राज गर्ग द्वारा अपने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को बदलने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने और स्वीकार करने का निर्णय राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था। पंजाब और हरियाणा (इसके बाद 'अपीलकर्ता' के रूप में वर्णित) और क्या प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उसकी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए दायर किया गया मुकदमा कायम रखने योग्य था, ऐसे प्रश्न हैं जो इस अपील में निर्धारण के लिए उठते हैं। 1996 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 901 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता।

2. प्रतिवादी नंबर 1 मार्च, 1973 में उप न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के रूप में सेवा में शामिल हुआ। उसकी जन्मतिथि सेवा पुस्तिका में 27.3.1936 दर्ज की गई थी क्योंकि वह मैट्रिक प्रमाण पत्र में उल्लिखित तिथि थी और पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के जवाब में उनके द्वारा किया गया एओएनएल उद्धरण। सेवा में शामिल होने के दस साल बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने पंजाब विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकारी को मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि में संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि उसकी सही जन्मतिथि 27.3.1938 थी लेकिन गलती से इसका दिनांक 27.3.1936 दर्ज किया गया। इस दावे के समर्थन में, प्रतिवादी नंबर 1 ने सरकारी हाई स्कूल, मूनक और हिंदू सभा हाई स्कूल, सुनाम द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया। विश्वविद्यालय की जन्मतिथि समिति ने सिफारिश की कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि को 27.3.1936 से बदलकर 27.3.1938 कर दिया जाए। सिंडिकेट द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रतिवादी क्रमांक 1 के मैट्रिक प्रमाण पत्र में आवश्यक परिवर्तन किये गये।

3. विश्वविद्यालय को उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को बदलने के लिए मनाने में सफल होने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में इसी बदलाव के लिए राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व किया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रतिवादी नंबर 1 की प्रार्थना को खारिज कर दिया और उन्हें पत्र दिनांक 28.1.1993 के माध्यम से इस बारे में सूचित किया गया।

4. प्रतिवादी संख्या 1 ने 1993 के सिविल सूट संख्या 417-ए में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी और एक घोषणा देने की प्रार्थना की कि राज्य सरकार और उच्च

न्यायालय का निर्णय दर्ज की गई जन्म तिथि को सही नहीं करना है। उनकी सेवा पुस्तिका अवैध, शून्य एवं अप्रभावी है। उन्होंने प्रतिवादियों को सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि को 27.3.1936 से 27.3.1938 में बदलने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने की भी प्रार्थना की।

5. प्रतिवादी नंबर 2 (यहां अपीलकर्ता) की ओर से दायर लिखित बयान में, पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1 के अध्याय II के अनुलग्नक-ए के पैरा 1 पर भरोसा किया गया था और यह दलील दी गई थी कि आवेदन द्वारा किया गया था। सेवा में प्रवेश करने के बारह वर्षों के बाद अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए प्रतिवादी नंबर 1 को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। आगे दलील दी गई कि विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि में सुधार करना उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

6. पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

"(1) क्या दिनांक 28.1.1993 का आदेश अवैध, अशक्त और शून्य है, जैसा कि आरोप लगाया गया है?OPP.

(2) क्या वादी प्रार्थना के अनुसार अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत पाने का हकदार है? OPP

(3)क्या वाद परिसीमा के अंतर्गत न होने के कारण पोषणीय नहीं है? OPD.

(4)क्या वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है? OPD

(5)क्या वादी को कार्यालय रिकॉर्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को चुनौती देने से रोका गया है? OPD.

(6)राहत।"

7. पक्षों की दलीलों और सबूतों पर विचार करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे पर फैसला सुनाया और घोषित किया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उसकी जन्मतिथि में सुधार के लिए दिए गए अभ्यावेदन को अस्वीकार करना अवैध और शून्य था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 की सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि को 27.3.1936 से 27.3.1938 तक बदलने के लिए एक अनिवार्य निर्देश भी जारी किया। सीमा के मुद्दे से निपटने के दौरान, विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने भारत संघ बनाम हरनाम सिंह (1993) 2 एससीसी 162 और सचिव और आयुक्त, गृह विभाग और अन्य बनाम आर. किरूबाकरन 1994 सप्लिमेंट में इस न्यायालय के निर्णयों को अलग किया। 1) एससीसी 155, निम्नलिखित अवलोकन करके:

> “मेरी राय में, ये प्राधिकारी जो नियमों/प्रशासनिक निर्देशों पर आधारित हैं, जो सीमा की अवधि निर्धारित करते हैं जिसके भीतर कर्मचारी अपने नियोक्ता को जन्मतिथि में सुधार के लिए अपना आवेदन जमा कर सकता है, जहां तक वर्तमान मुकदमे का संबंध है, निरर्थक हो गए हैं क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय ने अधिसूचना संख्या 11/4/93-5 पीपी-II/4499, दिनांक 21.6.1994 जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड-I, भाग-I में संशोधन करने के लिए नियम बनाए गए हैं। पंजाब सरकार उपरोक्त नियमों के लागू होने से दो साल की अवधि के भीतर जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदन कर सकती है। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दो फैसले वादी को सिविल कोर्ट में अपना उपचार मांगने से नहीं रोकते हैं और कम से कम मुकदमे को सीमाबद्ध नहीं बनाते हैं।"

8. निचली अपीलीय अदालत ने सभी मुद्दों पर ट्रायल कोर्ट से सहमति जताई और अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता और पंजाब राज्य द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई दूसरी अपील को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिन्होंने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री, जिसकी पुष्टि निचली अपीलीय अदालत ने की थी, कानूनी रूप से सही और उचित थी। परिसीमा के मुद्दे का निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किया गया:

> "अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि पंजाब सिविल सेवा नियम, जो वादी-प्रतिवादी पर लागू होते हैं, वर्तमान मुकदमे पर रोक लगाते हैं, क्योंकि यह सेवा में प्रवेश के बाद दो साल के भीतर दायर नहीं किया गया था, यह भी स्वीकार्य नहीं है . अधिसूचना दिनांक 21.6.1994 द्वारा, पंजाब सिविल सेवा नियमों में पंजाब सिविल सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, खंड- I भाग- I, 1994 के माध्यम से एक संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार कर्मचारी पहले से ही पंजाब सरकार की सेवा में है। संशोधित नियमों के लागू होने की तारीख इन नियमों के लागू होने से दो साल की अवधि के भीतर दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र आदि के आधार पर जन्म तिथि में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा, उन कर्मचारियों को एक मौका दिया गया, जिन्होंने सरकारी सेवा में प्रवेश से दो साल की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी जन्मतिथि को सही कराने का अवसर नहीं उठाया था और उन्हें दो साल की एक नई अवधि प्रदान की गई थी जो कि थी संशोधन की तिथि से प्रारंभ करें. अपीलकर्ताओं के वकील का तर्क, कि इस संशोधन को बाद में पंजाब सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव

(कार्मिक) के पत्र दिनांक 13.12.1995 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था, को उचित रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 1476, जिसका शीर्षक दलजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य है, में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को देखते हुए नीचे की अदालतें, जिसमें यह माना गया था कि केवल पत्र दिनांक 13.12.1995 के आधार पर उप सचिव द्वारा जारी, नियमों का संचालन स्थिर नहीं रह सकता है। इस प्रकार, उक्त संशोधन के मद्देनजर, वादी-प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे को परिसीमा से वर्जित नहीं कहा जा सकता है और अपीलकर्ताओं का तर्क है कि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि को सेवा में प्रवेश के दो साल के भीतर ही सही किया जा सकता है स्वीकार नहीं किया जा सकता।

9. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1 के अध्याय II के अनुलग्नक-ए का पैरा 1 (जैसा कि यह प्रतिवादी नंबर 1 के सेवा में शामिल होने के समय और उसके द्वारा दर्ज की गई जन्म तिथि में सुधार के लिए आवेदन करने की तारीख पर भी था) उसकी सेवा पुस्तिका), जिसका प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमे की स्थिरता से संबंधित मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है, इस प्रकार है:

"जन्मतिथि के संबंध में सरकारी सेवा में प्रवेश के समय या उसके प्रयोजन के लिए की गई आयु की घोषणा, प्रश्न में सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तब तक निर्णायक मानी जाएगी, जब तक कि वह अपनी दर्ज की गई आयु में सुधार के लिए आवेदन नहीं करता है। सरकारी सेवा में प्रवेश की तिथि से दो वर्ष के भीतर। हालाँकि, प्रशासनिक विभाग, कार्मिक एवं

प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से, सरकारी कर्मचारी के हितों के विरुद्ध किसी भी समय किसी सरकारी कर्मचारी की दर्ज की गई आयु में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जब वह संतुष्ट हो कि दर्ज की गई आयु उसकी सेवा पुस्तिका या राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की सेवा के इतिहास में गलत है और इसे इस उद्देश्य से गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि सरकारी कर्मचारी इससे कुछ अनुचित लाभ प्राप्त कर सकता है।

10. उपरोक्त पुनरुत्पादित नियम के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय या उसके प्रयोजन के लिए की गई आयु की घोषणा निर्णायक और सरकारी कर्मचारी पर बाध्यकारी है। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि सरकारी कर्मचारी सेवा में प्रवेश की तारीख से दो साल के भीतर उम्र में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा में प्रवेश के दो साल बाद उम्र में सुधार के लिए किए गए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका या इतिहास सेवा में दर्ज की गई उम्र को सही कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उम्र को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से इस तरह दर्ज किया गया है। वह कर्मचारी/अधिकारी को सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी सेवा में बने रहना पसंद है। बेशक, इस अभ्यास को करते समय, सक्षम प्राधिकारी ऑडी अल्टरम पार्टम के नियम का पालन करने और संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को दर्ज आयु/जन्मतिथि में प्रस्तावित परिवर्तन के खिलाफ अपने कारण का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर देने के लिए बाध्य है। दूसरे शब्दों में, जबकि सरकारी सेवक द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से दो साल के बाद अपनी दर्ज की गई उम्र में सुधार के लिए आवेदन करने पर पूर्ण प्रतिबंध है, सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय सुधार कर सकता है। यह पाया गया है

कि सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई आयु गलत है और संबंधित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी सेवा में बने रहने या कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है।

11. निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी नंबर 1 की जन्म तिथि, जो मार्च 1973 में सेवा में शामिल हुई, उसकी सेवा पुस्तिका में 27.3.1936 दर्ज की गई थी। ऐसा सेवा में भर्ती के उद्देश्य से प्रस्तुत आवेदन पत्र में उनके द्वारा की गई घोषणा और उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया था। कानून स्नातक होने के नाते, प्रतिवादी नंबर 1 को अपने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि यानी 27.3.1936 के बारे में पता होना चाहिए और यही कारण है कि उन्होंने लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत आवेदन पत्र में उस तिथि का उल्लेख किया होगा। यदि प्रतिवादी नंबर 1 की सही जन्मतिथि 27.3.1938 थी और यह उन स्कूलों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित था जहां उसने मैट्रिक परीक्षा में बैठने से पहले अध्ययन किया था, तो उसने सेवा में शामिल होने के तुरंत बाद एक आवेदन किया होता मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन किया और संबंधित प्राधिकारी को इस पर निर्णय लेने के लिए राजी किया ताकि वह अपनी सेवा में दर्ज जन्मतिथि में तदनुरूप बदलाव करने के लिए राज्य सरकार और उच्च न्यायालय का रुख कर सके। पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड I के अध्याय II के अनुलग्नक-ए के पैरा 1 के संदर्भ में पुस्तक। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने सेवा में प्रवेश करने के बाद दस साल से अधिक समय तक इंतजार किया और विश्वविद्यालय को दिनांक 27.10.1983 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपने दावे के आधार के रूप में स्कूल प्रमाणपत्रों का हवाला देकर मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि में परिवर्तन करने के लिए। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट को प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में मामले का फैसला करने में लगभग एक साल और तीन महीने लग गए और जनवरी/फरवरी 1985 में किसी समय मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि 27.3.1936 से

बदलकर 27.3.1938 कर दी गई। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को दिनांक 22.2.1985 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। आख़िरकार जानू में उनकी याचिका ख़ारिज कर दी गई।

12. इस न्यायालय ने बार-बार सिविल अदालतों और उच्च न्यायालयों को सेवा में प्रवेश करने के लंबे समय बाद दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे पर विचार करने और स्वीकार करने के प्रति आगाह किया है। भारत संघ बनाम हरनाम सिंह (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या नियोक्ता द्वारा सेवा में शामिल होने के पैंतीस वर्षों के बाद जन्मतिथि में सुधार के प्रतिवादी के अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था और क्या केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा उनके द्वारा दायर मूल आवेदन को अनुमति देना उचित था। ट्रिब्यूनल के आदेश को पलटते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

"एक सरकारी कर्मचारी, सेवा में प्रवेश के बाद, सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्राप्त करता है, जैसा कि राज्य द्वारा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि सेवाओं को इसमें निहित अन्य आधारों पर समाप्त नहीं किया जाता है। प्रासंगिक सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद। एक सिविल सेवक के सेवा रिकॉर्ड में दर्ज की गई जन्मतिथि इस कारण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सेवा में बने रहने का अधिकार सेवा रिकॉर्ड में इसकी प्रविष्टि के आधार पर तय होता है। एक सरकारी कर्मचारी जिसने रोजगार के प्रारंभिक चरण में अपनी आयु घोषित कर दी है, उसे निश्चित रूप से बाद में अपनी आयु में सुधार के लिए अनुरोध करने से नहीं रोका जा सकता है। एक सिविल सेवक के लिए अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा करना खुला है, यदि उसके पास

अपनी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य सबूत है जो पहले दर्ज की गई तारीख से भिन्न है और भले ही सुधार मांगने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। जन्मतिथि के संबंध में, सरकारी कर्मचारी को बिना किसी अनुचित देरी के ऐसा करना होगा। जन्मतिथि में सुधार के लिए नियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, लापरवाही या पुराने दावों के आधार पर राहत देने से इनकार करने का सामान्य सिद्धांत आम तौर पर अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा लागू किया जाता है। फिर भी सरकार को सेवा नियमों में एक समय-सीमा तय करने का अधिकार है, जिसके बाद किसी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, एक सरकारी कर्मचारी जो इस प्रकार निर्धारित समय के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करता है, वह अधिकार के रूप में अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई तारीख जन्म का विवरण स्पष्ट रूप से गलत है। परिसीमा का कानून कठोरता से लागू हो सकता है लेकिन इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और अदालतें या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता के लिए नहीं आ सकते हैं जो अपने अधिकारों को लेकर सोते हैं और परिसीमा की अवधि को समाप्त होने देते हैं। उमेस ने अपनी तिथि बदल दी (एससीसी पृ. 625-26, पैरा 4)

- “...एफ.आर. के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि।” हमारे निर्णय में 56(ए) का निर्धारण सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि इस आधार पर कि प्रतिवादी ने अपनी जन्मतिथि का दावा किया है, जब तक कि सेवा रिकॉर्ड को उचित प्रक्रिया के साथ लगातार सही नहीं किया जाता है। एक लोक सेवक सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि पर विवाद कर सकता है और रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन जब तक रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हो जाता, वह यह दावा नहीं कर सकता कि सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त

होने के कारण उसे संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत गारंटी से वंचित कर दिया गया है। ।"

(जोर दिया गया)

13. सचिव और आयुक्त, गृह विभाग और अन्य बनाम आर. किरुबाकरन (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास प्रतिवादी द्वारा उसकी जन्मतिथि में सुधार के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। सेवानिवृत्ति से पहले. प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा:

“जन्मतिथि में सुधार के लिए किसी आवेदन को न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा केवल संबंधित लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए नहीं निपटाया जाना चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के लिए ऐसे किसी भी निर्देश की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि उसके नीचे अपने संबंधित पदोन्नति के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे अन्य लोग इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। कुछ को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, यहां तक कि जन्मतिथि में सुधार के कारण, संबंधित अधिकारी, कुछ मामलों में वर्षों तक पद पर बना रहता है, जिसके दौरान कई अधिकारी जो वरिष्ठता में उससे नीचे हैं, अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। , हमेशा के लिए अपनी पदोन्नति खो सकते हैं। ऐसे मामले अज्ञात नहीं हैं जब कोई व्यक्ति अपने निकटतम वरिष्ठ की सेवानिवृत्ति की तारीख को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति स्वीकार करता है। हमारे अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे किसी लोक सेवक की जन्मतिथि में सुधार के संबंध में शिकायत की जांच करते समय अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जब तक प्रतिवादी द्वारा उन सामग्रियों के आधार पर, जिन्हें प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है, एक स्पष्ट मामला

नहीं बनाया जाता है, तब तक अदालत या न्यायाधिकरण को उन सामग्रियों के आधार पर कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जो केवल ऐसा दावा करते हैं। प्रशंसनीय. ऐसा कोई भी निर्देश जारी करने से पहले, अदालत या न्यायाधिकरण को इस बात से पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तविक अन्याय हुआ है और जन्मतिथि में सुधार के लिए उसका दावा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और तय समय के भीतर किया गया है। किसी नियम या आदेश से. यदि उस अवधि को निर्धारित करने वाला कोई नियम या आदेश नहीं बनाया गया है जिसके भीतर ऐसा आवेदन दायर किया जाना है, तो ऐसा आवेदन उस समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए, जिसे उचित माना जा सकता है। - आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ऐसे दावे का समर्थन, जो उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य सबूत हो सकता है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न उठता है, तो जिम्मेदारी आवेदक, पीआर की होती है

(जोर दिया गया)

14. भारत संघ बनाम सी. रामा स्वामी (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने, अखिल भारतीय सेवाओं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16-ए के गहन विश्लेषण के बाद, पारित आदेश को उलट दिया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की हैदराबाद पीठ ने प्रतिवादी की जन्मतिथि में बदलाव का निर्देश दिया था और कहा था:

15. उपर्युक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि सेवा में शामिल होने के बारह वर्षों के बाद अपनी सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर किया गया मुकदमा स्पष्ट रूप से गलत था और ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी नंबर 1 और निचली अपीलीय अदालत के पक्ष में डिक्री पारित करके एक गंभीर गलती की और उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को रद्द करने से इनकार करके उसी गलती को दोहराया। विद्वान निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने

भी अधिसूचना दिनांक 21.6.1994 द्वारा नियम में किए गए संशोधन पर भरोसा करके एक त्रुटि की, जिसने सरकारी कर्मचारी को अगले दो वर्षों के भीतर जन्म तिथि में सुधार की मांग करने में सक्षम बनाया। यह न तो प्रतिवादी नंबर 1 का दलील वाला मामला है और न ही उसकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि 1994 में किया गया संशोधन पूर्वव्यापी था या उसके ग्राहक ने 21.6.1994 के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया था। बल्कि, न्यायालय के प्रश्न के जवाब में, विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके मुवक्किल ने 1985 में पहली और आखिरी बार सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया था, जब विश्वविद्यालय ने उनके सुधार के लिए उनके आवेदन पर विचार किया और मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि स्वीकार कर लिया।

16. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाता है। ट्रायल कोर्ट और निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को भी रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। आमतौर पर, हम प्रतिवादी नंबर 1 पर लागत का बोझ डालते, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हमने ऐसा करने से परहेज किया है।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आटिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेश कुमार II (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।